

नविवारक नरिध

[स्रोत: हदिसुतान टाइम्स](#)

चर्चा में क्यों?

भारत के सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने मुरुतुजा हुसैन चौधरी बनाम नगालैंड राज्य, 2025 में पुनः पुष्टि की कि [नविवारक नरिध एक कठोर उपाय है](#), जिसके लिये संवैधानिक और वैधानिक सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन आवश्यक है।

- इस फैसले में उचित औचित्य के अभाव तथा कानूनी सदिधांतों का उल्लंघन करने के कारण नगालैंड के नरिध आदेशों को रद्द कर दिया गया।

नविवारक नरिध के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का नरिणय क्या है?

- मामला: दो व्यक्तियों को मादक पदार्थ जबती के बाद स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार नविवारण अधिनियम, 1988 (PITNDPS अधिनियम) के तहत नविवारक रूप से हरिसत में लिया गया था, जो पुलसि के इस आरोप पर आधारित था कि रूहिा किये जाने पर वे फरि से तस्करी शुरू कर देंगे, लेकिन इसके लिये कोई अलग आधार नहीं था।
- सर्वोच्च न्यायालय का नरिणय: सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि हरिसत आदेशों में पृथक, वशिषिट आधारों का अभाव होने के कारण PITNDPS अधिनियम की धारा 6 का उल्लंघन हुआ है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने टपिपणी की कि हरिसत में लिये गए ऐसे लोग जो अंगरेजी नहीं समझते थे, उन्हें मौखिक रूप से उनकी भाषा में जानकारी दी गई, लेकिन इसे अपर्याप्त माना गया। सर्वोच्च न्यायालय ने हरकिसिन बनाम महाराष्ट्र राज्य (1962) मामले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि हरिसत के आधार के बारे में केवल मौखिक संचार अपर्याप्त है।
- न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि [नविवारक नरिध से मूल अधिकारों](#) पर प्रभाव पड़ता है और इसमें वैधानिक मानदंडों का सख्ती से पालन करना चाहिये। परिणामस्वरूप, न्यायालय ने नरिध आदेशों को रद्द कर दिया।

नविवारक नरिध क्या है?

- परिचय: इसका तात्पर्य संभावित गैर-कानूनी गतविधियों को रोकने के क्रम में किसी व्यक्तिको [बना सुनवाई](#) के हरिसत में लेना है।
 - दंडात्मक नरिध के विपरीत (जिसमें उचित प्रक्रिया और दोषसदिधा नयिमें का पालन किया जाता है) नविवारक नरिध के तहत संदेह के आधार पर व्यक्तगत स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया जाता है।
- संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 22 के अंतर्गत गरिफतारी तथा नरिध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसका पहला भाग आपराधिकि जाँच से जुड़े सामान्य वधिकि मामलों से संबंधित है जबकि दूसरा भाग नविवारक नरिध से संबंधित है।
 - किसी व्यक्तिको बना विचारण के तीन माह तक हरिसत में रखा जा सकता है, जब तक कि सलाहकार बोर्ड (जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिये अरुहति व्यक्त शामिल होते हैं) द्वारा अवधान बढ़ा दी जाए।
 - हरिसत में लिये गए व्यक्तिको हरिसत में लिये जाने के कारणों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए, जब तक कि इससे सार्वजनिकि हति को नुकसान न पहुंचे। उन्हें वधिकि प्रतनिधित्व का अधिकार है, हालाँकि कुछ मामलों में इस अधिकार को प्रतबिधित किया जा सकता है।
- नविवारक नरिध से संबंधित प्रमुख कानून:
 - राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980: राष्ट्रीय सुरक्षा और लोक व्यवस्था को खतरे से बचाने के लिये नज़रबंदी की अनुमतिकि प्रावधान।
 - वधिविदिध क्रिया-कलाप (नविवारण) अधिनियम, 1967: भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को खतरा पहुँचाने वाली गतविधियों की रोकथाम किये जाने का प्रावधान।
 - लोक सुरक्षा अधिनियम, 1978: इसका उपयोग जम्मू-कश्मीर में लोक व्यवस्था और सुरक्षा के आधार पर नविवारक नरिध के लिये किया जाता है।
 - न्यायिकि नरिणय: अमीना बेगम बनाम तेलंगाना राज्य (2023) में, सर्वोच्च न्यायालय ने नरिणय दिया कि नविवारक नरिध एक असाधारण उपाय है और इसका मनमाना रूप से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
 - जसीला शाजी बनाम भारत संघ मामले (2024) में, सर्वोच्च न्यायालय ने नरिणय दिया कि बिंदियों को उनकी हरिसत में आक्षेप करने हेतु उचित अवसर सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/preventive-detention-7>

